(Rs. in lakhs)

S. No.	Name of the Unit	Amount Outstanding
1.	M/s Pearl Drinks Ltd., Delhi	4.18
2.	M/s Pure Drinks, Delhi	47.18
3.	M/s Delhi Bottling Company, Delhi.	91.80
4.	M/s Parle Beverage Ltd., Bombay	103.88
5.	M/s Pure Drinks, Bombay	5.00 (penalty)
6.	M/s Dukes & Sons Ltd., Bombay	85.44

(d) Necessary administrative, legal and other measures under the relevant laws/ Acts are continuously taken to recover the outstanding dues. Courts are also requested for expeditious hearing and early vacation of stay orders.

Agriculture and Rural Development Banks under Banking Regulation Act

*137. SHRI JOYANTA ROY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are seriously thinking to bring all the Agriculture and Rural Development Banks under Banking Regulation Act; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

विमानपत्तनों की अधिशेष भूमि को पट्टे पर देने के संबंध में अनियमितताएं

*138. **श्री गोविन्दराम गिरी:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानपत्तनों की अधिशेष भूमि को पट्टे पर देने के मामले में, इस संबंध में कोई ठोस नीति न होने के कारण बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हैदराबाद और अहमदाबाद विमानपत्तनों में बरती गई अनियमितताओं संबंधी जांच रिपोर्ट में सतर्कता अधिकारी को तत्काल इस संबंध में कोई नीति बनाने के लिये कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस जांच रिपोर्ट पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इसमें दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) जून, 1984 में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग) के मुख्य सतर्कता अधिकारी से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें हैदराबाद हवाई अड्डे पर एक निजी पार्टी को होटल परिसर के निर्माण के लिये भूमि पट्टे पर दिये जाने में हुई कतिपय अनियमितताओं का उल्लेख था। रिपोर्ट में, हवाई अड्डा भूमि को पट्टे पर दिये जाने के लिये एक निश्चित नीति तैयार किये जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया था।

चूंकि रिपोर्ट की जांच से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कुछ सेवा निवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामले का पता चला, इसलिये मामले को अगस्त, 1995 में गहन छानबीन के लिये केन्द्रीय